ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

भारत में फार्म के आकार अनुसार संस्थागत साख का विश्लेषण

Analysis of Institutional Credit by Farm Size in India

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 20/10/2021, Date of Publication: 24/10/2021

रोजी मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग,
एम.एम.एच. कॉलेज
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु साख महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यही अवधारणा कृषि क्षेत्र के संदर्भ में भी सत्य है। कृषि साख एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती साधन है जो कृषि उत्पादन, उत्पादकता को प्रभावकारी रूप से प्रभावित करती है अतः कृषि साख की समय-अनुसार उचित दर, सुगमता एवं पर्याप्त उपलब्धता कृषि विकास की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत लेख में भारत में कृषि संस्थागत साख स्रोतों की संरचना इनकी प्रवृत्तियां एवं संस्थागत साख का फार्म आकार के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है इस हेतु प्रस्तुत शोध पत्र में पैनल डाटा का प्रयोग किया गया है जिसमें अलग-अलग वर्षों में(वर्ष 2013 एवं वर्ष 2020) में फार्म आकार के आधार पर वर्गीकृत कृषकों की संस्थागत साथ में गणनित प्रतिशत के आंकड़ों को लिया गया है।

Credit plays an important role for the development of any sector of the economy, the same concept is also true in the context of agriculture sector. Agricultural credit is an important intermediate means that effectively affects agricultural production, productivity, so timely, reasonable rate, accessibility and adequate availability of agricultural credit are essential for the sustainable growth of agricultural development.

In the present article, an attempt has been made to analyze the structure of agricultural institutional credit sources in India, their trends and institutional credit in the context of farm size, for this, panel data has been used in the present research paper, in which farmers classified on the basis of farm size in different years (year 2013 and year 2020). The figures of percentage calculated with the institutional have been taken.

मूलशब्दः किसान, कृषि ऋण, कृषि वित्त, कृषि साख, वित्तमाध्यम, वित्त संस्थान।
Keywords: Farmers, Agriculture Credit, Agricultural Finance, Agricultural Credit, Finance Medium, Financial Institutions.

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि क्षेत्र का बुनियादी महत्व है। भारत के प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा अंश भूमि का है और कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग लगभग 42.6 प्रतिशत कृषि क्रियाओं में संलग्न है । अतः कृषि क्रियाएं अभी भी लोगों के रोजगार(आजीविका)का प्रमुख स्रोत है भारत की लगभग 20प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादकृषि क्षेत्र से उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही तथा अन्य योजना अवधि में कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि प्रतीत हुई है , परंतु कृषि क्षेत्र का स्थिरता के साथ विकास महत्वपूर्ण है इसके अलावा समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन अति आवश्यक है देश के आर्थिक विकास को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में उचित दरों, समयानुसार एवं पर्याप्त उपलब्धता के साथ मध्यवर्ती साधन के रूप में कृषि साख की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक है।

इस शोध पत्र में कृषि संस्थागत साख स्रोतों की संरचना, प्रवृतियां एवं संस्थागत साख का फार्म के आकार के अनुसार विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

संस्थागत साख संरचनाः

कृषि साख मुख्यतः संस्थागत एवं गैर संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होती है। भारत में संस्थागत साख संरचना को निम्न वर्गीकरण द्वारा चित्रित किया गया हैः

संस्थागत-साख संरचना :

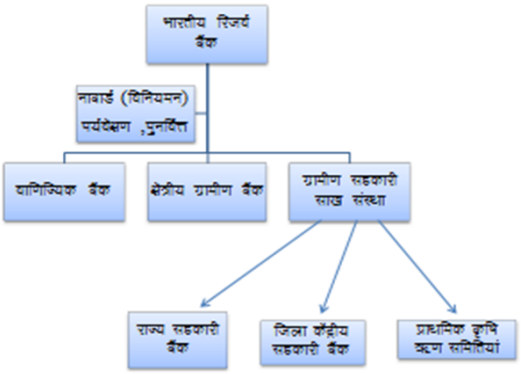

कृषि संस्थागत साख की प्रवृतियां

विभिन्न संस्थानों का सापेक्षिक अंश

निम्नांकित तालिका में कृषि हेतु विभिन्न संस्थागत साख की प्रवृत्तियों का सापेक्षिक अंश दिया गया है इसमें आर्थिक सुधारों से पूर्व एवं पश्चात की प्रवृत्तियों को बताया गया है

तालिका-1

वर्ष	सहकारी बैंक(%)	वाणिज्यिक बैंक (%)	ग्रामीणसहकारी बैंक(%)	कुलसाख(करोड रूपए में)
1980-81	61.6	38.4	NA	3292
1990-91	49.0	47.6	3.4	9830
2000-01	39.4	52.6	8.0	52827
2010-11	16.7	73.8	9.5	468291
2020-21	15.1	72.1	12.8	1500000

स्रोत:राकेश मोहन एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली मार्च 18 2006 टेबल एक तालिका एक पृष्ठ संख्या 101 से तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनामिक सर्वे 2012-13 तालिका 557 पेज वन 11

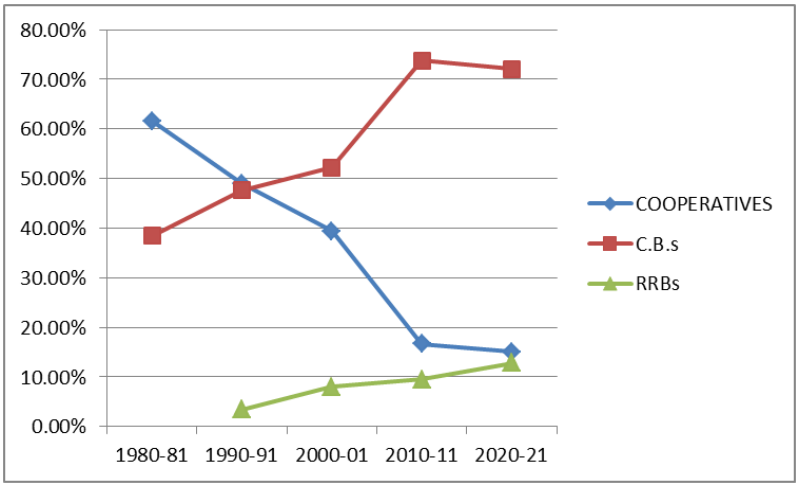

उपर्युक्त तालिक.1 में 1980-81 में वाणिज्यिक बैंकों का कृषि वित्त में हिस्सा 38% था जो 2020-21 में बढ़कर 72.1 प्रतिशत हो गया इसके परिणामस्वरूप सहकारी समितियों का संस्थागत वित्त में हिस्सा

जो 1981 में 61.6 प्रतिशत था जो 2020-21 में कम होकर लगभग 15.1 प्रतिशत रह गया। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रश्न है उन्होंने संस्थागत कृषि वित्त का 8 से 10 प्रतिशत प्रदान किया है। तालिका में 1980-81 तथा 1990-91 के मध्य अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में संस्थागत साख के प्रभाव पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि कुल कृषि साख(जिसमें वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक) का लगभग 3 गुना वृद्धि हुई (आर्थिक सुधारों के पूर्व)। वहीं यदि 2000-01 से 2020,-21 के मध्य अवधि के दौरान यह वृद्धि लगभग 28 गुना रही है। अतः कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान(आर्थिक सुधारों के पश्चात) कृषि क्षेत्र में संस्थागत साख के प्रभाव में उल्लेख वृद्धि दर्ज की गई है।

फार्म के आकार अनुसार संस्थागत साख का विश्लेषण

यहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संस्थागत साख में फार्म के आकार के अनुसार किसका अंश ज्यादा है अर्थात कौन इस वृहत संस्थागत साख का लाभ उठा रहा है इस हेतु वर्ष 2013 तथा वर्ष 2020 के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन निम्नांकित तालिकाओं द्वारा किया गया है

तालिका-2 संख्या; (000)

फार्म का आकार(हेक्टेयर)	परिचालन होल्डिंग की कुल संख्या	संस्थागत ऋण लेने वाले परिचालन होल्डिंग की अनुमानित संख्या	परिचालन होल्डिंग की अनुमानित संख्या का प्रतिशत (संस्थागत साख का परिचालन होल्डिंग की संख्या से अनुपात)
सीमांत(<1हेक्टेयर)	64316.37	12631.81	19.64
छोटे(1-1.99)	18776.33	6167.85	32.84
अर्धमध्यम(2-3.99)	11217.9	3875.76	34.54
मध्यम(4-9.99)	15335.50	2104.32	39.43
बड़े(10 औरज्यादा)	1003.43	402.07	40.06
कुल	100649.54	25181.80	25.01

एग्रीकल्चरलस्टेटस एट ए ग्लांस 2013

वर्ष 2013

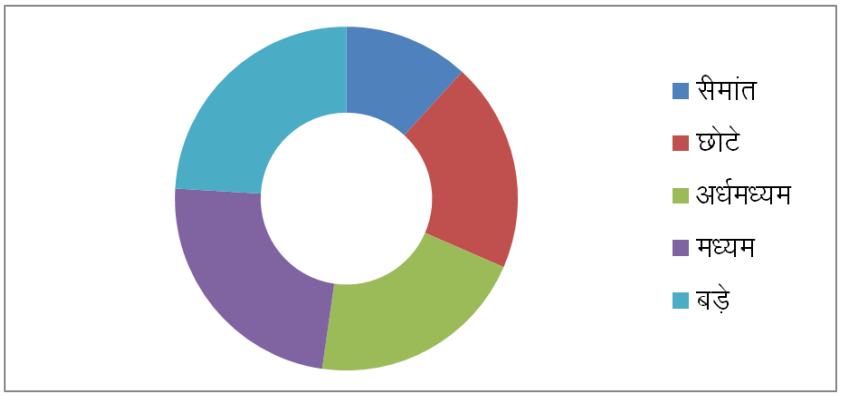

उपर्युक्त तालिका के द्वारा ज्ञात होता है कि अनुमानित परिचालन होल्डिंग का केवल 19.64%सीमांत (जो 1 हेक्टेयर से कम)कृषकों से संबंधित है जिन्होंने कृषि उद्देश्य के लिए संस्थागत ऋण लिया था एयही अन्य फार्माकारों के अनुसार वर्गीकृत कृषकों यथा छोटेए अर्धमध्यम एमध्यम तथा बड़े का इस संस्थागत साख में प्रतिशत क्रमश32.84%,34.54%,39.43% तथा 40.06% रहा , यही संपूर्ण देश की बात करें तो तालिका.2 से ज्ञात होता है कि कुल अनुमानित परिचालन होल्डिंग में से मात्र लगभग25% ने कृषि उद्देश्य हेतु संस्थागत साख प्राप्त किया है

अतः स्पष्ट होता है कि कुल परिचालन होल्डिंग के लगभग 75% ने संस्थागत साख का लाभ नहीं उठाया है ।

इसी संदर्भ में वर्ष 2020 के आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं , जिसे तालिका.3 में दर्शाया गया है ;-

तालिका.3

फार्म का आकार(हेक्टेयर)	परिचालन होल्डिंग की कुल संख्या	संस्थागत ऋण लेने वाले परिचालन होल्डिंग की अनुमानित संख्या	परिचालन होल्डिंग की अनुमानित संख्या का प्रतिशत (संस्थागत साख का परिचालन होल्डिंग की संख्या से अनुपात)
सीमांत(<1हेक्टेयर)	100098	33806	33.77
छोटे(1-1.99)	25772	12616	48.95
अर्धमध्यम(2-3.99)	13963	7153	51.22
मध्यम(4-9.99)	5538	3068	55.39
बड़े(10औरज्यादा)	819	437	53.35
कुल	146190	57080	39.04

स्रोत:एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020

तालिका-3 अभिज्ञानित होता है कि सीमांत कृषकों से संबंधित अनुमानित परिचालन होल्डिंग जो वर्ष 2013 में 19.64% था वह वर्ष 2020 में बढ़कर 33.77% हो गया अर्थात वर्ष 2013 से 2020 की अवधि के दौरान सीमांत कृषकों द्वारा संस्थागत साख (जो कृषि उद्देश्यों के लिए है) में वृद्धि 2.67 गुना हुई है यही अन्य फार्म आकारों के अनुसार वर्गीकृत कृषकों यथाय छोटे और अर्ध-मध्यम, मध्यम तथा बड़े आकार का इस वृहद संस्थागत साख में अंश क्रम से लगभग 49% तथा 51% तथा 55% रहा है वर्ष 2013 एवं वर्ष 2020 के मध्य-अवधि के दौरान सभी फार्म आकारों के अंश में क्रम से छोटे आकार में लगभग 2 गुना, अर्ध- मध्यम आकार में लगभग 1.85 गुना, मध्यम आकार में लगभग 1.5 गुना एवं बड़े आकार में लगभग 1.1 गुना वृद्धि दर्ज की गई है यदि संपूर्ण देश की बात करें तो यह 2013 में जो लगभग 25% था अब यह 2020 में लगभग 39% हो गया जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उद्देश्य हेतु संस्थागत साख का वर्ष 2013 में 25% ने लाभ उठाया तथा 2020 में अनुमानित परिचालन होल्डिंग में कृषकों ने लगभग 39% ने लाभ उठाया इस संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है

वर्ष2020

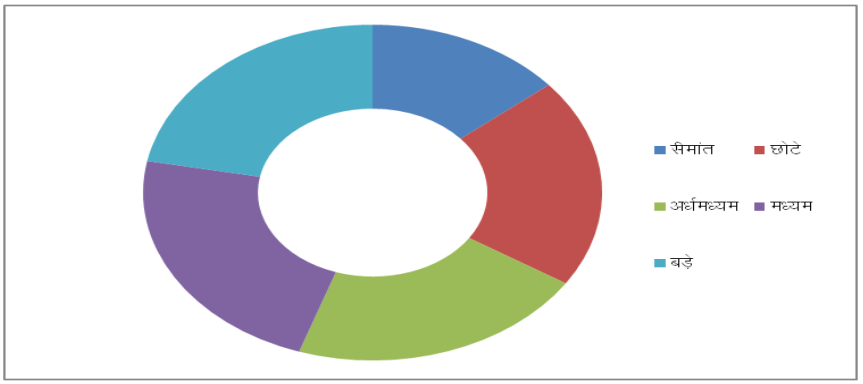

तालिका–4

फार्मआकार (हेक्टेयर्स)	संस्थागतसाख की सौंपई मात्रा			अल्पकालीन ऋण			
	अल्पकालीनसाख	मध्यम कालीनसाख	दीर्घकालीनसाख	बीजफर्टिलाइजर की मात्रा का मूल्य	अन्य साधनों(INPUTS) की मात्रा का मूल्य	कुलनकदलीगईराशि	कुल
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9(6+7+8)
(<1.00)छोटे	1959872.91	530878.34	268994.93	305528.65	56406.28	1597937.99	1959872.91
(1.0-1.99)अर्ध मध्यम	1281948.16	388801.81	246649.71	197097.63	40352.95	1044497.58	1281948.16
(2.0-3.99)अर्ध मध्यम	1123167.76	335450.41	324918.60	179968.24	42247.50	900952.01	1123167.76
(4.0-9.99)मध्यम	821381.28	306984.09	432030.10	141487.12	39358.51	640535.64	821381.28
(10 &>)बड़े	213982.23	92075.62	152396.00	39599.49	11029.19	163353.55	213982.23
(सभीवर्ग)	**5400352.34**	**1654190.27**	**14249989.34**	**863681.14**	**189394.44**	**4347276.76**	**5400352.34**

स्रोत:एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2013

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-9* October (Part-1) 2021
Innovation The Research Concept

तालिका–5

फ़ार्म आकार (हेक्टेयरमें)	संस्थागतसाख की लीगई मात्रा			अल्पकालीन ऋण			
	अल्पकालीन साख	मध्यम कालीनसाख	दीर्घकालीन साख	दीगइफर्टिला इजर की मात्रा का मूल्य	अन्य साधनों(INPUTS) की मात्रा का मूल्य	कुलनकदलीग ईराशि	कुल
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9
(<1.00)छोटे	13752050	3373150	819622	1612319	869829	11269903	13752050
(1.0-1.99)अर्ध मध्यम	8392012	2428182	646128	1086480	528083	6777450	8392012
(2.0-3.99)अर्ध मध्यम	6673044	2055348	755189	785825	426471	5460748	6673044
(4.0-9.99)मध्यम	4257710	1483165	640092	510623	281246	3465841	4257710
(10 &>)बड़े	890230	276255	174263	98835	72398	718997	890230
(सभीवर्गों)	**33965047**	**9616101**	**3035293**	**4094082**	**2178027**	**27692938**	**33965047**

स्रोत:एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020

उपर्युक्त बालिकाओं से ज्ञात होता है कि सभी बैंकों द्वारा संवितरित कुल अल्पकालीन (उत्पादन साख) संस्था के साथ में से सीमांत कृषकों द्वारा उठाए गए लाभ का वर्ष 2013 में वर्ष 2020 में क्रम से 36.3% तथा 40.4%रहा है तथा छोटे अर्ध मध्यम मध्यम एवं बड़े आकार वालों का प्रतिशत वर्ष 2013 में क्रम से 23.7% ,20.8 %, 15.2% तथा 4% रहा है। यही आंकड़ा वर्ष 2020 के लिए छोटे कृषकों के लिए 24.7% अध-मध्यम कृषकों के लिए 19.6% मध्यम कृषकों के लिए 12.5% तथा बड़े आकार वाले कृषकों के लिए 2.6% रहा । वर्ष 2020 में कुल अल्पकालीन साथ में से संवितरित नगद का प्रतिशत लगभग 81.5% रहा जो वर्ष 2013 में लगभग 80.5% था। अतः इसे लगभग 1% वृद्धि हुई। बाकी 18.5%(वर्ष 2020) फर्टिलाइजर एवं अन्य इनपुट्स का प्रतिशत रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

यह अध्ययन संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह के वितरण में असमानता की जांच करने के लिए किया और संस्थागत ऋण के उपयोग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान के लिए किया गया था।

निष्कर्ष

कृषि के आधुनिकीकरण में और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए साख की एक बड़ी भूमिका है। भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए संस्थागत साख में तीव्र वृद्धि हुई है। यह कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी कदम है ,क्योंकि यह किसानों को आवश्यक उपकरण एवं अन्य आदानों को खरीदने के लिए मदद करता है संस्थागत ऋण प्रभाग के उच्च लक्ष्यों की स्थापना के साथ साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करना , निसंदेह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र को तीव्र तनाव से बाहर निकालने में मदद की है, जिसका उन्होंने अतीत में सामना किया था। यद्यपि तालिका 2 तालिका 3 तथा तालिका 4 एवं 5 से विदित होता है कि संस्थागत साख का लाभ उठाने वाली परिचालन होल्डिंग्स का निम्न प्रतिशत(देश में कुल होल्डिंग में से) अभी भी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, अर्थात सीमांत एवं छोटे कृषकों की संस्थागत साख में प्रतिशत अभी भी कम है तथा इनका कुल परिचालन होल्डिंग्स का लगभग 82.5% (वर्ष 2013) में था। संस्थागत साख में सीमांत एवं छोटे किसानों के प्रतिशत में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि कृषि विकास के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. *अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, एक नज़र में कृषि सांख्यिकी, (1970 से 2008 तक वार्षिक अंक) कृषि और सहकारिता मंत्रालय, सरकार।*
2. *भारत सरकार, नई दिल्ली। भारत सरकार (2004) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
3. *गोलेत, रमेश (2007) भारत में कृषि ऋण में वर्तमान मुद्दे: एक आकलन,*
4. *राकेश (2004) भारत में कृषि ऋण : स्थिति, मुद्दे और भविष्य का एजेंडा, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, नवंबर।भारतीय रिजर्व बैंक समसामयिक पत्र, 28, संख्या 1. कुमार, अंजनी, सिंह, धीरज के. और कुमार, प्रभात (2007) ग्रामीण ऋण का प्रदर्शन और क्रेडिट स्रोतों की पसंद को प्रभावित करने वाले कारक,*
5. *नाबार्ड डेटाबैंक (विभिन्न मुद्दे) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई।*
6. *दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (2008ए) भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, 2007-08,*